

आयुक्त (अपील) का कार्यालय, Office of the Commissioner (Appeal),

केंद्रीय जीएसटी, अपीलं आयुक्तालय, अहमदाबाद Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.

CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015



DIN: 20221264SW0000555A59

स्पीड पोस्ट

क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STP/1851/2022-APPEAL

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-002-APP-71/2022-23 दिनाँक Date : 30-11-2022 जारी करने की तारीख Date of Issue 08.12.2022 आयुंक्त (अपील) द्वारा पारित Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals)

- य Arising out of Order-in-Original No. CGST/A'bad North/Div-VII/ST/DC/168/2021-22 दिनॉक: 17.03.2022, issued by Deputy/Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad-North
- ध अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address
 - 1. Appellant

M/s Travel Designer India Pvt. Ltd. B-1402, Mondeal Heights, Nr. Wide Angle Cinema, S.G.Highway, Ahmedabad-380015

Respondent
 The Deputy/ Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad
 North, 4th Floor, Shahjanand Arcade, Memnagar, Ahmedabad - 380052

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India :

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप—धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- (i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- (ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- (ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a varehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of approcessing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

1

- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उद्दर्शदन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ख) . यदि शुल्का का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इएँ–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।
 - The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35—वी/35—इ के अंतर्गतः—
 - Under Section 35B/35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) उक्तिलिखित परिच्छेद २ (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण <u>(सिस्टेट)</u> क्री पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन ,असरवा ,गिरधरनागर,अहमदाबाद —380004
- (a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor,Bahumali Bhawan,Asarwa,Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(7) सीमा शुंल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कं एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपीलों के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत संनवैट क्रेडिट की राशि:
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.
- ⇒ 'यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- `(ii) 🕖 amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती **है।**

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Travel Designer India Pvt. Ltd., B-1402, Mondeal Heights, Nr. Wide Angle Cinema, S.G. Highway, Ahmedabad — 380015 (hereinafter Mondeal Heights, Nr. Wide Angle Cinema, S.G. Highway, Ahmedabad — 380015 (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-in-Original No. CGST/A'bad-North/Div-vII/ST/DC/168/2021-22 dated 17.03.2022 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner, Central GST, Division VII, Ahmedabad North (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

- 2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are engaged in business of providing Hotel Accommodation, Transfer and Sightseeing in India & abroad to the Indian Agents on Rezlive.com, i.e., B2B Online reservation system, and is holding Service Tax Registration No. AACCT1252CST001. The appellant is private limited company registered under the Companies Act, 2013 and is wholly owned subsidiary of foreign Travel Designer DMCC (hereinafter referred to as "the principal of the appellant").
- During the audit of the financial records of the appellant, for the period from April-2016 to June-2017, conducted by the officers of the Central GST, Audit Commissionerate, Ahmedabad, the following observation was raised in Revenue Para 2 & 3 of Final Audit Report:
 - (a) Revenue Para 2: During the course of audit and scrutiny of the record of the appellant, it has been noticed that they have shown Rs. 19,24,850/- as Bank Guarantee Charges recovery in the balance sheet for the FY 2016-17. On further verification, it has been found that the appellant has provided bank guarantee to the client for as if any default occurs they may utilized the same and for the same, they recovered some amount from the client as an intermediary and shown the same as "Bank Guarantee Charges recovery" in the balance sheet. Further as per Rule 9(c) of the Place of Provision of Services Rules, 2012, place of service shall be location of the service provider. Therefore, the appellant has to pay the service tax along with interest and penalty on the said amount.
 - (b) Revenue Para 3: During the course of audit and scrutiny of the record of the appellant, it has been noticed that they have shown Rs. 7,77,966/- as Corporate Guarantee Charges recovery in the balance sheet for the FY 2016-17. On further verification, it has been found that the appellant has provided corporate guarantee to M/s. Travel Designer, DMCC, Dubai, as to enable them to enhance their credit limit in the banks and the appellant have provided the service as an intermediary. Further as per Rule 9(c) of the Place of Provision of Services Rules, 2012, place of service shall be location of the service provider. Therefore, the appellant has to pay the service tax along with interest and penalty on the said amount.

The above observation were not accepted by the appellant, hence a SCN bearing No. 12/C-IV/Audit/AP-23/20-21 dated 26.10.2021, was issued to them proposing demand of

Service Tax amount of Rs. 4,05,421/- in terms of proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 and proposing penalty under Section 78 of the Finance Act, 1994. The said SCN was adjudicated vide impugned order and the demand of Rs. 4,05,421/- proposed in SCN was confirmed under the proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 and penalty of Rs. 4,05,421/- was also imposed on the appellant under Section 78 of the Finance Act, 1994.

- 3. Being aggrieved with impugned order, the appellant have filed the present appeal under Section 85 of the Finance Act, 1994 along with the application dated 05.07.2022 seeking condonation of delay.
- 4. Personal hearing in the matter of application for condonation of delay was held on 25.11.2022. Shri Brij Shah, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellant for personal hearing. He reiterated the submission made in his application for condonation of delay filed on 05.07.2022.
- 5. On going through the appeal memorandum, it is noticed that the impugned order was issued on 17.03.2022 and the same was received by the appellant on 24.03.2022. The present appeal, in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, was filed on 07.06.2022. The appellant, vide letter dated 05.07.2022, requested to grant them condonation of delay in filing appeal in Form ST-4, inter alia, submitting that they have filed appeal in Form ST-4 within 3 months from the communication of order as provided in Para 2 of the Preamble of the impugned order.
- 6. It is observed that the relevant Section 85 of the Finance Act, 1994, provides that the appeal should be filed within a period of 2 months from the date of receipt of the decision or order passed by the adjudicating authority. I find that the appellant is registered with Service Tax and is a Private Limited Company. They are required to be aware of the provisions of the Finance Act, 1994 and cannot take shelter of the clerical mistake appearing in the preamble of the impugned order.
- 7. Further, under the proviso appended to sub-section (3A) of Section 85 of the Act, the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay or to allow the filing of an appeal within a further period of one month thereafter, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal with in the period of two months. Relevant text of Section 85 is reproduced below:

"SECTION 85: Appeals to the Commissioner of Central Excise (Appeals).—

- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority subordinate to the Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise may appeal to the Commissioner of Central Excise (Appeals).
- (2) Every appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.



(3) An appeal shall be presented within three months from the date of receipt of the decision of the decision of the decision of the decision of such adjudicating authority, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter made before the date on which the Finance Bill, 2012, receives the assent of the

Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appeal within the aforesaid appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of three months.

(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision of order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 receives the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter:

Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appeal within the aforesaid appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month."

- 8. I find that in terms of Section 85, the limitation period of two months for filing the appeal in the present cases starts from 25.03.2022 and the appellant were required to file the appeal on or before 24.05.2022. However, the appeal was filed on 07.06.2022 that too without showing sufficient cause for such delay. It is also noticed that the application for condonation of delay in filing the appeal was filed on 05.07.2022, i.e. after one month of last day of filing the appeal that too without showing any reasonable cause for such delay and taking shelter of the clerical mistake in the preamble of the impugned order.
- 9. It appears that legal provisions relating to condonation of delay was taken very casually and presumed that condonation of delay will be granted as a matter of right without any proper explanation.
- 10. I find that the appellant, in the facts and circumstances discussed above, has not been explained the sufficient cause for condoning the delay. Accordingly, I reject the application seeking condonation of delay. Hence, the appeal has also to be rejected.
- 11. In view of the above discussion and well settled law, without expressing any opinion on the merits of the case, I reject the appeal filed by the appellant on the grounds of limitation.

12. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

.. 30 % NO VEWSEY 20 (Akhilesh Kumar)

Commissioner (Appeals)

Date: 30.11.2022

(R. C. Maniyar)

Atteste

Superintendent (Appeals),

CGST, Ahmedabad



By RPAD / SPEED POST

To,

M/s. Travel Designer India Pvt. Ltd.,

Appellant

B-1402, Mondeal Heights,

Nr. Wide Angle Cinema, S.G. Highway,

Ahmedabad -380015

Respondent

The Deputy Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad North

Copy to:

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- 2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad North
- 3) The Deputy Commissioner, CGST, Division VII, Ahmedabad North
- 4) The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad North (for uploading the OIA)

5) Guard File

6) PA file



